

प्रेषक,

अतर सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2015

विषय: लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सचल चिकित्सा वाहनों हेतु माह मार्च एवं अप्रैल, 2015 के बीजकों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सं0-16प/वाहन/5/2008/20223, दि0 18.8.2015 एवं पत्र सं0-16प/वाहन/5/2008/20224, दिनांक 27.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत 11 जनपदों में संचालित सचल चिकित्सा वाहनों हेतु पी0पी0पी0 पार्टनर द्वारा उपलब्ध कराये गये माह मार्च, 2015 एवं अप्रैल, 2015 के बीजक की धनराशि कमश ₹18,79,085/- एवं ₹ 42,78,441/- अर्थात् कुल ₹61,57,526/- (रुपये इकसठ लाख सत्तावन हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र) धनराशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसका भुगतान मै0 जैन वीडियो ऑन व्हील्स प्रा0लि0 के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त संस्था को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून जिम्मेदार होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.4.2015 में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तों तथा योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार के Non-Performance (गैर-निष्पादन) की दशा में नियमानुसार कटौती कर ली गयी है।
4. धनराशि का आहरण वितरण एवं व्यय मितव्ययता को ध्यान में रखकर वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही नियमानुसार किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।
5. भविष्य में धनराशि के प्रस्ताव के साथ सभी जनपदों की औचक निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि प्रस्ताव के साथ समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पूर्व इंगित कमियों को ठीक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं तदनुसार कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वाहनों में स्टॉफ की अनुपलब्धता एवं मशीनों के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को स्टॉफ की उपलब्धता एवं खराब मशीन को तत्काल ठीक कराने हेतु नोटिस दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।



8. सचल चिकित्सा वाहनों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा समयबद्ध कार्यवाही न की जा रही हो, तो अनुबन्ध के शर्तों के अधीन उसके विरुद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।
9. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुसार समीक्षा एवं आडिट की कार्यवाही समय-समय पर की जाय एवं शासन को तदनुसार अवगत कराया जाय।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य, 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण, 99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पी.पी.पी. मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 168(P)/XXVII(3)/2015, दिनांक 27 अगस्त, 2015 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

अलॉटमेंट आई0डी0-S1508120177

भवदीय,

(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव

संख्या-1739(1)/XXVIII-5-2015-08/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. मैसर्स डा0 जैन वीडियो ऑन व्हील्स नई दिल्ली- 110 016
- ✓ 7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3 एवं 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा है,  
(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव।